THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (c). There may be changes in membership of the Planning Commission. No major change in the functions of the Planning Commission is contemplated.

(b) Yes, Sir.

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPOREANCE

REPORTED UNEARTHING OF A LONG DISTANCE CALL RACKET IN DELHI

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे वक्तव्य दें :

"दिल्ली में दूरस्थ स्थानों को टेलीफोन करने का अवध धन्धा करने वाले लोगों के गिरोह का पता लगने के समाचार।"

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): विभाग को टेलीफोन उपभोक्ताओं से ऐसी शिकायतें मिली थी कि उन्हे संदेह है कि बेईमान कर्मचारियों की सांठ-गांठ से उनकी टेलीफोन लाइनों से अनधिकृत काल किए जा रहे हैं। इस तरह की हर शिकायत के मिलने पर विभाग इस बात का पता लगाने के लिए उचित जाच-पड़ताल करता रहा है कि क्या ऐसी कोई शरारत की जा रही है। किन्तु इसे सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नही मिले थे। तथापि सन्देह कुछ पक्के होने के कारण कुछ समय पहले कुछ कर्मचारियों की दिल्ली से बाहर बदली कर दी गई थी।

हाल ही में जनता के किसी व्यक्ति से कुछ सूचना मिलने पर विभाग ने कुछ और विस्तृत सूचना एकत्रित की और उसकी तथा केंद्रीय जाच ब्यूरो (सी० बी० आई०) के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की सहायता से 4 जून, 1971 को उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाने की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम-स्वरूप एक लाइनमेन और एक मजदूर को मुखबिर का जयपुर के लिए लम्बी दूरी की काल की पैशकश करते और बम्बई के काल के लिए टेलीफोन उपभोक्ताओं की लाइनों को एक दूसरे से बदलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने इन दोनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। उनके मामलों में आगे कार्रवाई की जा रही है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसी शरारत इसी कारण से होती है कि कुछ बेईमान टेलीफोन उपभोक्ता निम्न-ग्रेड कर्मचारियों को ऐसी अनधिकृत कार्य करने के लिए प्रलोभन देते है। विभाग ऐसे भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रयत्न कर रहा है।

विभाग को ऐसी शरारत की संभावना के बारे में बहुत चिन्ता है, क्योंकि इससे किसी निर्दोषक उपभोक्ता को अनावश्यक नुकसान हो सकता है। इस संबंध में ध्यानपूर्वक जांच करने के परिणामस्वरूप कई कदम उठाए गए हैं, मिसाल के तौर पर मीटर कक्ष को ताला लगाना और मीटरों पर सील करना। लाइनों के वितरण प्वाइंटों को जहां से कि काल को आसानी से दूसरी लाइन पर डाला जा सकता है, उत्तरोत्तर खम्बों पर और अधिक ऊंचा किया जा रहा हैं, ताकि लाइनों तक पहुंच ज्यादा कठिन हो जाए। काफी बड़ी संख्या में वितरण प्वाइंटों को ऊंचा कर दिया गया है और अन्य को उत्तरोत्तर

ऊंचा किया जा रहा है। वितरण प्वाइंट बक्से को ताला लगाने का भी एक प्रयोग किया जा रहा है।

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से में जानना चाहता हूं कि बेचारा टेलीफून का बक्सा तो इन्नोसेन्ट है और ताला भी बड़ा इन्नोसेन्ट है लेकिन हिन्दुस्तान के जितने अवैध व्यापार करने वाले हैं, चाहे वे ब्लैकमार्केटीयर्स हो, चाहे सट्टा खोलने वाले हो, चाहे मटका खोलने वाले हो परन्तु कुछ अधिकारी अच्छे भी है जो कि उनपर काबू पाना चाहते है लेकिन उनको जान से मार देने की धमकी दी जाती है। जब मटका पजाब मे और बम्बई में खुलता है तो मुझे पता है कि इन्दौर जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल से बाकी सब कालें बन्द कर दी जाती है और उन लोगो को लाइटेनिंग काल दी जाती है। सारा मटके का धधा, लाखों रुपए का अवैध व्यापार टेलीफून डिपार्टमेन्ट से किसी भी ढग से होता है और अगर कोई अफसर उसको रोकने की कोशिश करे तो कुछ पाकेट ट्रेड यूनियन्स होती हैं अथवा कुछ चौकीदार यूनियन होती है जो कि अवैध व्यापार करने वालो की होती हैं और जो कुछ धर्म के नाम पर ट्रेड यूनियन बनती है वे इमानदार अफसरों के खिलाफ तार भेजती है कि यह अफसर करप्ट है, इसको बदल दिया जाये क्योकि वे अवैध व्यापार करने वालों को कन्ट्रोल करना चाहते हैं। सारे देश भर में जितना सट्टे का काम है उसके लिए लाइनें हमेशा बिल्कुल खाली रहती है भले ही मिनिस्टर की लाइन एंगेज रहे। यही नहीं, इनके खिलाफ ग्वालियर में एक पत्रकार ने लिख दिया कि यह मटका जालंधर से खुलता है और इस तरह से टेलीफोन के जरिए उनको खबरें मिलती है तो उस आदमी को झूठे कत्ल के केस में जालंधर में फंसा दिया गया। इसी तरह से आगरा के एक पत्रकार को फंसा दिया गया। तो इस डिपार्टमेन्ट के जरिए ब्लैकमार्केटीयर्स जिस तरह से नाजायज फायदा उठाते हैं, ये मटकेबाज और सट्टेबाज जो है, मैं चाहता हूं खास तौर पर सरकार उनपर ध्यान दे और उनके खिलाफ सी. बी. आई. की इन्क्वायरी हो। और धर्म के नाम पर तथा पाकेट यूनियन, जो इस तरह की ट्रेड यूनियन्स चलती है उनको खत्म किया जाये ताकि ईमानदार अफसर काम कर सकें और उन लोगो का सजा मिले जो कि अब तक इस प्रकार का ब्लेक का व्यापार करते आ रहे है। यह आपेन चीज है जोकि कई बार अखबारों में आ चुकी है और उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है लेकिन यह मटका और सट्टा व्यापार सरकार खत्म नही कर सकी है। इसपर सरकार सख्त कार्यवाही करे—यही मैं जानना चाहता हू।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य को जो जो चिन्ता है काले बाजार, सट्टे बाजार वगैरह वगैरह बाजारों की, मैं भी उनकी चिन्ता में अपने को सम्मिलित करता हू लेकिन टेलीफोन विभाग के पास ऐसा कोई जरिया नही है कि वह कालर की इन्टेन्शन को पहले से समझ ले कि किस पर्पज के लिए वह काल बुक कर रहा है इसलिए लाइटेनिंग काल जिसका दाम करीब करीब 8 गुना ज्यादा होता है नार्मल काल से, वह एक हाई प्रायर्टी काल है, किसी को भी उसे करने का अधिकार है और अगर वह करता है तो उसमें लाचारी है। लेकिन यह पहला मौका है जब हमने उस सतर्कता को ध्यान में रखते हुए ताकि हमारे विभाग के लोग उपभोक्ताओं के साथ मिल जुल करके कोई गलत कामों में सम्मिलित न हों इस तरह की बात पकड़ी है और 4 जून को उनके पकड़े जाने से स्वयं विभाग में काफी हलचल मची हुई है।

[श्री शशि भूषण]

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि किसी यूनियन के कहने से हो तो चाहे धर्म के नाम पर, यूनियन हों या अधर्म के नाम पर, यूनियन के कहने से किसी व्यक्ति का ट्रान्सफर करने की नीति हमारी नहीं है और जबतक मैं यह काम देख रहा हूं, मुझे पूरी आशा है कि कोई यूनियन इस तरह का काम करके हमको प्रेशराइज नहीं कर सकेगी। ... (व्यवधान)...

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : I have carefully read the statement given by the hon. Minister. I am thankful that he laid a trap to catch some people. But the reply he has given seems to convey the impression that he is not aware of the extent to which this racket prevails; he says in his statement : 'no conclusive evidence was forthcoming to establish such mischief'. It is entirely incorrect to say so, Hundreds of complaints come to the department that calls which they never made are being entered in their bills and no action has been taken against the person concerned. I can give the instance of a call of my own brother. Dr. Hori Lal Saksena, Tel. No. 42753. He was given a bill which included a sum of Rs. 22.50 for making a call to Dehra Dun. When he complained that he did not make any call to Dehra Dun the officer wrote to him that he regretted that there was a wrong call entered in his bill and that he was giving him a revised bill. When the officer said that a wrong call was entered, did you find out who was the person who made the wrong entry ? And was he given an exemplary punishment ? Did you also trace the person who had actually made the call to Dehra Dun and had got it entered in my brothers bill ? Was he punished ? Was his telephone disconnected ? This is the l ast you could have done to stop the racket.

I have another instance which I wish to bring to the notice of the House. My brother received a telephone bill in which a sum of Rs. 100 was charged for entries in the Telephone Directory for 1970. My brother asked for details for the entries, but though two months have passed, no details have been sent. Instead of that, a wire was sent to him saying that the Bill "is herewith returned to avoid disconnection of the phone, and refund, if any, intimated by the D. O. will be adjusted in the next bill."

What is worse still, complaints are not kept on the file. They are returned and only the action taken is intimated.

Such instances are happening not only in Delhi but all over India. For instance the Telephone Department in Gorakhpur, sent me a bill several years ago in which they charged Rs. 200 for Trunk calls which I had not made. I complained and they were corrected, but I do not know if anything has happened to the persons concerned. I am sorry that some blacksheep in the department should bring the name of the staff into disrepute. Although I am a trade unionist, I have no sympathies for such black sheep, and they must be dealt with in a harsh manner. I also want that such subscribers whose calls are thus entered in others' bills should have their phones disconnected.

Lakhs of rupees are thus being misappropriated. I hope the hon. Minister who, I know, is a very efficient person, will see to this and clean the whole department. He must stop all these wrong things happening in the department. I hope the hon. Minister will do it.

SHRI H. N. BAHUGUNA : Sir, I am beholden to the hon. Member for giving me information about these things and about his telephone. But I am sorry to say that it would be much better if he sends a letter in writing, pointing out all these things to me.— and I shall also be greatful to him,— so that I may really go into them in fuller details. Presently, I do not have all the facts regarding that case with me, because they do not arise out of this particular question. Therefore, I am sorry I have to disappoint him by saying that presently I have nothing to comment upon.

MR. SPEAKER : He has just quoted an instance ; not an individual case but some instances. So, you might reply.

SHRI H. N. BAHUGUNA : So far as this is concerned, my hon. friend will agree with me that this is because of the instructions given that this particular type of case has been apprehended. It is I think about a month now since I have been in this Ministry. Two instances were brought to my notice ; one in Jammu and Kashmir, and the other in Delhi. We had issued definite instructions as to how to seal this leakage and how to give a more efficient and honest service to our customers. So, a number of steps have been taken and more are intended to be taken. As it is, these linesmen, when they go on duty, they have a pass with them. We propose to give them now a new style work pass for that day, for such and such area and for such and such duty, so that he can be apprehended, and you can find out if he was really on duty or was really committing pilferage.

Similarly, so far as the bills are concerned, which are not normally correct bills, because, somebody, if I may say so, pilfered the calls from a particular number, we always go into the details and if we are satisfied that the past bills relate to arrears, it will be indicative which cannot be otherwise explained, and we do give some rebate. That might have been the case of giving a rebate and action taken.

So far as the question of the person making the entry is concerned, now it is an automatic entry. The meter notes automatically, and notes down the reading. Nobody need read it manually. Therefore, I cannot honestly punish the meter. Somebody may make the meter run, may be surreptitiously, and it is this particular thing which is not always known to us. Now that we have come to grips with it, and now that we have arrested these two people, I am more than sure that the cooperation of this House will give us fuller strength to meet with the situation.

श्री अमर नाथ चावला : (दिल्ली सदर) अध्यक्ष महोदय, मैं ऐंटी करप्शन विभाग की सराहना करना चाहता हूं कि जो बहुत अर्से से यह रैकेट चल रहा था उस को उन्होंने पकड़ा कई सालों से प्राइवेट सब्सक्राइबर्स की यह कमप्लेन्ट आ रही थी कि कई महीनों के अन्दर उन के बिल एकदम जम्प कर जाते थे और इस के लिए उन्हों ने दरख्वास्तें भी दीं, उस के ऊपर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर विभाग कार्यवाही करता तो शायद पहले ही वह पकड़ में आ जाते। इस के ऊपर मंत्री महोदय क्या कोई जांच बैठाने का वायदा करेंगे ?

मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि सट्टा व्यापारियों को जो टेलीफोन कनेक्शन दिये जाते हैं इस इल्लीगल ट्रेड के लिये, क्या ऐज़ सच उन को आप डिबार करेंगे कि वह टेलीफोन कनेक्शन न ले सकें, जैसा कि फतेहपुरी में बहुत से व्यापारी ऐसा काम करते हैं ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : अध्यक्ष जी, पहले क्या होना था, यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अब ऐसा न होने दें यह हमारा अथक प्रयास रहेगा।

जहां तक फतेहपुरी के सट्टे बाजार का सवाल है, मेरे मित्र जो होम मिनिस्ट्री में हैं उन से हम सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे कि किस तरह से सट्टा व्यापारियों पर हम नज़र रख सकते हैं।

12.16 hrs.

RE : RELIEF MATERIAL FOR BANGLA DESH REFUGEES

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Sir, with your permission, I would like to draw the attention of the house and the Government to a very serious bit of news which has appeared in yesterday's Calcutta papers to the effect that a very large quantity—several hundred tonnes—of relief material which had been received from various foreign countries and agencies for the relief of Bangla Desh refugees, is lying uncleared at the Dum Dum airport. A photograph also has been published, and the report says that from Denmark, Canada, the United Nations, and